[श्री सत्यपाल मलिक]

कलंक की बात होगी । इस का प्रदर्शन कर के हम अपनी पहली आजादी के हीरो को इस तरह से बदनाम कर रहे हैं । बहुत-बहुत शुक्रिया ।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SAT PAUL MITTAL): Now I shall request Mr. Buddh Priya Maurya to move the Motion of the President's Address.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य (आंध्र प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे महामना राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये आज्ञा प्रदान की है । साथ ही साथ श्रीमन् मैं आभारी हूं अपने दल के नेता का जिन्होंने यह जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली । मैं अपने कर्त्तव्य को अधूरा निभाऊंगा यदि सदन के नेता के प्रति मैं अपना आभार प्रकट नहीं करता ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि "राष्ट्रपति के प्रति निम्नलिखित रूप में कृतज्ञता ज्ञापित की जाये :—

'राष्ट्रपति ने 18 फरवरी 1983 को संसद् की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में कृपया जो अभिभाषण दिया है उसके लिए राज्य सभा के सदस्य जो सभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित हैं राष्ट्रपति के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं ।' "

श्रीमन्, बीसवीं शताब्दी में जनतंत्र और संसदीय प्रणाली के सिद्धान्तों से प्रेरणा लेकर बहुत से पिछड़े राष्ट्र बहुत से प्रगतिशील राष्ट्र आजाद हुए । इन सिद्धांतों पर चल कर अपने निश्चय की प्राप्ति की ओर चल पड़े । लेकिन हमारे देखते-देखते थोड़े से ही समय में उन राष्ट्रों में से बहुत से इस प्रणाली से हट गये । कहीं फौजी तानाशाही आ गई और कहीं जनतंत्र ने, संसदीय प्रणाली ने फीताशाही का रूप धारण कर लिया । श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम को अपने राष्ट्र के नेताओं से जनतंत्र की धरोहर मिली है । जितना बड़ा जनतंत्र भारत का जनसाधारण लेकर चल रहा है भारत का बुद्धिजीवी लेकर चल रहा है उतना बड़ा जनतंत्र दुनिया में और किसी देश की जनता लेकर नहीं चल रही है । एक तरह से हम अभिमान कर सकते हैं कि दुनिया में जनतंत्र के अग्रवा राष्ट्रों में हमारी गिनती आती है । लेकिन श्रीमन्, चुनावों का बहिष्कार, राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार, राज्यपालों के भाषणों का बहिष्कार कुछ विरोधी दलों की कार्यकारिणी का विशेष अंग बन गया है । यह चलन जनतंत्र और संसदीय प्रणाली को कमजोर करता है । राष्ट्रपति संसद के विशेष अंग हैं । लोक सभा तथा राज्य सभा की जब बैठक नहीं होती तो संसद की पूर्ण शक्ति दोनों सदनों की पूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में आ जाती है । राष्ट्रपति के प्रति इस प्रकार की प्रतिक्रिया, चाहे जितने बड़े सिद्धांतों द्वारा चलने वाला दल हो, इस समय मुझे क्षमा करेंगे यह कहने के लिये, वे दल राष्ट्रपति का अपमान करते हैं और एक तरह से संविधान का अपमान करते हैं ।

महामहिम राष्ट्रपति ने अपने भाषण के प्रारम्भ में कुछ शब्द कहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनको मैं यहां पर पढ़ कर कोट करना चाहूंगा :

"आने वाला वर्ष हमारे लिये चुनौतियों और अवसरों से भरा हुआ है जिसके

लिये संसद्, सरकार और जनता को मिलजुलकर काम करना होगा।

श्रीमन्, सबसे ऊंचे स्थान से आवाज आई है, उन्होंने चुनौतियों को किसी विशेष दल से नहीं जोड़ा है। उन्होंने उपलब्धियों को भी किसी दल से नहीं जोड़ा है। उन्होंने एक प्रकार से जो देश के सामने और देश के जनतंत्र के सामने नाना प्रकार की चुनौतियां हैं उसके लिए उन्होंने आह्वान किया है। संसद् को भी इशारा किया है, सरकार को भी और जागृत किया है जनसाधारण को भी। क्षेत्रीय भावनाओं में फंस कर लगातार क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काया जा रहा है। क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काया जा रहा है। भाषा की आड़ में अलगाव को बढ़ावा दिया जा रहा हैं। देश की अखंडता खतरे में पड़ गई है। सत्याग्रह के ऐतिहासिक हथियार को हिंसा की धार देकर, कानून को बलाये ताक रख कर, मानवता के खून से होली खेली जा रही है। आसाम के नर-संहार ने जो अवैधानिक आन्दोलन की देन है, उसने भारत की आत्मा को झकझोर दिया है। श्रीमन्, मैं इस संदर्भ में परम पूज्य बाबा साहिब डाक्टर अम्बेदकर को कोट करना चाहूंगा। यह समय की पुकार थी और कांग्रेस के नेताओं की दुरन्देशी थी कि उन्होंने एक शोषित सर्वहारा समाज में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जो विद्वता में अपना विशेष स्थान रखता था, जो हमारे देश के बुद्धिजीवियों में विशेष स्थान रखता था, उनको संविधान की मसौदा बनाने वाली समिति का अध्यक्ष बनाया और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री की हैसियत से उस मसौदे को संवैधानिक रूप देने के लिए उन पर जिम्मेवारी सौंपी। कांस्टिट्यूएन्ट ऐसेम्बली के वोल्यूम 12 के पृष्ठ 978 से मैं पढ़ रहा हूं। जिस समय संविधान पूरा हो गया उस समय उन्होंने अपना आखिरी प्रवचन किया, उसको मैं कोट कर रहा हूं —

"If we wish to maintain democracy, not merely in form but also in fact, what must we do? The first thing, in my judgment, that we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. It means, we must abandon the bloody method of revolution. It means that we must abandon the method of civil disobediance, non-cooperation and 'satyagraha'. When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional methods. But where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the grammer of anarchy and the sooner they are abandoned, the better for us."

श्रीमन्, यह उस महापुरुष की आखिरी इच्छा थी कि उन रास्तों पर जाने के लिए जनतंत्र और संसदीय प्रणाली में कोई स्थान नहीं है जो एक तरह से हिंसा को भड़काते हैं, जो एक तरह से राष्ट्रीय सम्पत्ति का विनाश करते हैं जो एक तरह से क्षेत्रीय भावनाओं को भड़का करके जनसाधारण की हत्या का आवाहन करते हैं। इस तरह के आन्दोलनों को हमेशा के लिए तिलांजलि दे देनी चाहिए। जनतंत्र की प्रणाली के शरीर में चुनाव का चलन जान है। जान को मारकर शरीर को बचाया नहीं जा सकता। हर जीवित समाज और हर जीवित राष्ट्र की समस्याएं होती हैं। बहस-मुबाहिसा करके, विचार-विमर्श करके, विचारों का आदान-प्रदान करके समस्याओं का हल खोजा जाना चाहिए। लेकिन समस्याओं की आड़ में कानून को बलाये ताक रख कर हिंसा को भड़काना, राष्ट्र की सम्पत्ति को नष्ट करना तथा बेगुनाह इंसानों की जान से खेलना बिलकुल

[श्री बुद्ध प्रिय मौर्य]

प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के बाहर की बात है। कोई भी सरकार इस प्रकार की हरकतों को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज हमारे देश के उत्तर पूर्वी अंचल में साम्प्रदायिकता तथा क्षेत्रीयता को आधार बनाकर हिंसा को भड़काया जा रहा है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ जिम्मेदार दल और उनके नेता इस आग में एक तरह से तेल डालने का काम कर रहे हैं। इस आग में इस तरह से तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी उन तमाम खामियों को जिनका परिणाम कल हुआ, परसों हुआ, मजबूती से उसका विरोध करके उसको नहीं दबाया। गुरुओं की भूमि पंजाब में धर्म की आड़ में तनाव और अलगाव की भाषा बोली जा रही है। वह गुरु जिन्होंने आह्वाहित किया मानवता के लिये, वह पंजाब की भूमि जिसके भगतसिंह जैसे वीर ने देश की आजादी के लिये अपनी जान दे दी, फांसी का तख्ता चूम लिया, आज वहां दुर्भाग्य से धर्म की आड़ में तनाव और अलगाव को भड़काया जा रहा है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां विदेशी एजेंसियां काम कर रही हैं और वे एक तरह से साजिश कर ही है कि इस देश की एकता को किस तरह से तोड़ा जाय। असम, पंजाब तथा अन्य क्षेत्रों के लिये अवैधानिक आंदोलन, कांग्रेस (आई) का नहीं, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का नहीं बल्कि यह देश के जनतंत्र देश की अखंडता और देश के भविष्य का निर्णय करने जा रहें हैं। मेरा निवेदन है श्रीमन्, कि ऐसी परिस्थिति में और विशेष तौर से एक ऐसे समाज, एक ऐसे राष्ट्र जहां पर बहुत सी भाषायें बोली जाती हों, जहां पर करीब करीब दुनिया के सभी धर्मों के मानने वालों की बड़ी तादाद बसती हो, इस तरह के राष्ट्र के लिये, इस तरह के समाज के लिये केन्द्र का शक्तिशाली होना अति अनिवार्य है। मैं इस विचारधारा का हूं। 1935 के गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट ने केन्द्र को शक्ति दी थी, काश कि आजाद होने के बाद संविधान के द्वारा हम केन्द्र को और ज्यादा शक्तिशाली बना सकते। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं और ये समस्यायें भयंकर रूप धारण करके हमारे सामने आ गई। असम को लेकर कल बहुत चर्चा हो चुकी है। माननीय गृह मंत्री जी का भाषण हो चुका है। विरोधी दलों के नेताओं के भी इस सदन में और उस सदन में विचार आ चुके और आज माननीय गृह मंत्री अपनी ओर से उत्तर भी देंगे। मैं असम की समस्या पर ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन मैं यह निवेदन जरूर करना चाहता हूं जिस बारे में राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में भी जिक्र किया है। असम की समस्या के पीछे कुछ ऐसे कारण हैं जिनको जानना अनिवार्य है। कल साम्यवादी नेता की ओर से यह विचार आया था कि 1978 में चुनाव हुए। लेकिन 1978 के चुनाव के वक्त विदेशियों की समस्या सामने नहीं आई। क्यों? इसका उत्तर तो आज उन विरोधी दलों को देना होगा जो आज असम की समस्या को लेकर असम में अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं। उसके बाद गोहाटी में चुनाव हुए, लोकल बाडीज, कारपोरेशन के। उसमें एक विशेष दल के व्यक्ति मेयर बने। प्रतिक्रिया हुई और इस वजह से यह समस्या खड़ी की गई है। मैं यह कहता हूं कि कुछ विदेशी मिशनरियों का इसमें हाथ है। उन्होंने तरह-तरह से इसके लिये लोगों को भड़काया है। मैं किसी भी दल के नेता या किसी दल की राजभक्ति के बारे में कुछ नहीं कहता, यह मेरे जैसे इंसान को शोभा नहीं देता। हर दल

और हर दल के नेता राजभक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कभी-कभी समस्या को वे इस ढंग से सोचते हैं जिससे समस्या उलझ जाती है। यह आरोप लगाया गया कि हम संविधान का संशोधन करना ही नहीं चाहते थे। यह हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि हम चुनावों को थोपना चाहते थे लेकिन जब गृह मंत्री जी अपना उत्तर देंगे उसमें यह तमाम विवरण आएगा। हमारी इस नीयत पर शक करना गलत है बल्कि अगर हमारी सरकार चाहती तो धारा-356 का उपयोग कर सकती थी लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान रखते हुए कि इसकी दूसरे क्षेत्रों में बुरी प्रतिक्रिया हो सकती है क्लाज-5, आर्टिकल 356 का सहारा नहीं लिया। हमने कभी यह नहीं कहा, हमारे दल के नेता ने कभी यह नहीं कहा कि सभी विरोधी दलों ने चुनाव का विरोध किया। हमने कभी यह नहीं कहा और हम ने यह भी कभी नहीं कहा कि सभी विरोधी दलों ने संविधान के संशोधन का विरोध किया। हमने हमेशा एक ही बात कही है कि इन दोनों मसलों पर विरोधी दल एकमत नहीं थे, उनमें आपस में विभाजन था। मैं तो यह कह देना चाहता हूं। आज उन लोगों से, उन लोगों को अपनी गिरेबान में हाथ डाल कर सोचना पड़ेगा कि इन्होंने चुनाव का विरोध कर के क्या आन्दोलनकारी जो कानून से खेल रहे थे उन्होंने क्या उस भावना को भड़काया नहीं। चुनाव का विरोध फौजी तानाशाह करते हैं चुनाव का विरोध वे शक्तियां करती हैं जो जनतंत्र के वातावरण में नहीं पले होते। दुर्भाग्य है कि दल के नेता जो जनतंत्र की दुहाई देते हैं उन्होंने चुनाव का विरोध किया और आज तरह तरह के आरोप लगा दिये। यह इतना ज्यादा गम्भीर विषय है इसमें मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन यह निश्चयपूर्वक कह देना चाहता हूं कि जो कुछ भी निर्मम हत्याएं हुई हैं जो कुछ भी बेगुनाह मारे गये हैं आसाम के अन्दर जो कुछ भी राष्ट्रीय सम्पत्ति का विनाश हुआ है उसकी जिम्मेदारी पूरे तौर से उन लोगों के ऊपर आती है जिन्होंने संविधान के संशोधन में सरकार का साथ नहीं दिया और उसके बाद चुनाव का विरोध किया। यह उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है। श्रीमन्, जहां तक . . .

श्री सदाशिव बागाईतकर (महाराष्ट्र) : श्रीमन् मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय मौर्य साहब हमारे सामने लाए हैं। जिस विषय पर चर्चा अभी अधूरी है और जिसके ऊपर चर्चा अभी पूरी होनी है जिसमें लोगों को बोलना है उसको दृष्टिगत रख कर उनको आसाम का जिक्र करने का अधिकार है इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति यह है कि जो लांछन या आक्षेप वह अपोजीशन पर ला रहे हैं वह उचित नहीं है क्योंकि उस पर अभी तक पूरी बहस नहीं हो पाई है। (**व्यवधान**) मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं। यह बात पच्चासों बार सदन में उठी है, हम लोगों के सामने अपोजीशन में मतभेद था या नहीं। यह बात नहीं है कि अपोजीशन में मतभेद हैं, आप हमें जानते है और हम भी जानते हैं जहां तक संविधान में संशोधन करने की बात थी दो तिहाई बहुमत शासक दल को था कि नहीं और यह बात कल भी मैंने उठाई थी कि जिन लोगों ने आपको आश्वासन दिया था कि हम समर्थन करेंगे उन लोगों का यदि सहयोग लेकर चलेंगे तो दो तिहाई बहुमत आपके पास था इसलिए मैं नहीं समझता कि यह उचित है कि जिस बहस को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है उस मुद्दे को आप उठाते रहें।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतपाल मित्तल) : इसमें प्वाइन्ट आफ आर्डर की कोई गुंजाइश नहीं है।

This is what we had said yesterday and he has a right to say this. You cannot stop him. He is not laying blame on any particular organisation in the opposition even though he is entitled to do that also. Let him continue his speech.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह नहीं है कि विरोधियों ने उकसाया उनको (व्यवधान) यह अभिभाषण पर बोलें (व्यवधान) उनकी सीमा से बाहर न जाएं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAT PAUL MITTAL): Will you agree to a similar request from this side also that when you speak on this Motion on the President's Address you should not say a word against the Government? Do not deny him that right. We cannot deny him that opportunity.

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं, झा साहब के सुझाव से शुरू करना चाहता हूं। मैं राष्ट्रपति को ही कोट कर रहा हूं, पन्ना "6" पैरा 17 और 18 और यहीं से आगे फिर प्रारम्भ करूंगा।

"अब मैं देश की अंदरूनी राजनीतिक स्थिति की ओर जाता हूं। फूट डालने वाली और विघटनकारी ताकतें हिंसा भड़काने और राष्ट्रीय ढांचे को कमजोर करने में लगी हुई हैं। इनका मुकाबला दृढ़ता के साथ किया जाना चाहिए। असम और पंजाब जैसे मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श से विरोधी दलों को शामिल करने के लिए सरकार ने पहल की है और यह सराहनीय प्रवृत्ति जारी रहनी चाहिए, बहुत से क्षेत्रों में साम्प्रदायिक और राष्ट्र-विरोधी तत्व आपत्तिजनक गति-विधियों में लगे हुए हैं। इनको कारगर ढंग से दबाना होगा। उत्तर पूर्वी कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उग्रवादी संगठन सरगर्म हैं। इनकी गतिविधियों से निपटने तथा शांति और सामान्य स्थिति बनाये रखने के लिए हमने अच्छे तालमेल के साथ एक अभियान चलाया है। इसी बीच पूरे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में विकास कार्यों की गति को बढ़ावा गया है।"

मेरा यह दुर्भाग्य कहा जाए या सौभाग्य कि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा और कानून का भी। इसलिए अलग नहीं जाऊंगा, जो तथ्य है उनसे। श्रीमन मैं कहना चाहता हूं कि लगातार इस सदन में और सदन के बाहर, हमेशा आरोप लगाये गये हैं कि इस 35 वर्ष की आजादी में कोई उपलब्धि नहीं हुई। हमारे देश में करीब 185.8 मिलियन हैक्टेयर भूमि में खेती हो सकती है। इसमें से केवल 142.9 मिलियन हैक्टेयर भूमि में खेती होती है। लगभग 43 मिलियन हैक्टेयर भूमि बेकार पड़ी हुई है। इसको 20 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर लगातार 1971, 72 से खेत मजदूरों में बांटा गया है और उसको बांटा जा रहा है। हमने यह निश्चय किया है कि इस कार्य को अलग 10 वर्षों के अन्दर पूरा कर दिया जायेगा। केवल 38 मिलियन हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है, 104.9 मिलियन हैक्टेयर भूमि देश में बिना सिंचाई के है श्रीमन्। छठी पंचवर्षीय योजना में हमने यह निश्चय किया है कि हर वर्ष कम से कम तीन मिलियन हेक्टेयर

भूमि को सिंचित किया जाए। 20 सूत्री कार्यक्रम का विशेष अंग है कि हर वर्ष कम से कम 3 मिलियन हैक्टेयर भूमि को सींचने के योग्य बनाया जाए। यह मानव समाज के इतिहास में अद्वितीय मिसाल है जो निश्चय 20 सूत्री कार्यक्रम के बीच में किया गया है। अन्न का उत्पादन जिस समय अंग्रेज इस भारतवर्ष को, टूटे-फूटे भारतवर्ष को, एक असहाय भारतवर्ष को शोषण की ज्वाला में जलते हुए छोड़कर गये। उनको अंग्रेजों को कांग्रेस के नेतृत्व ने, उन वीरों ने जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कुरबानी देकर इस देश से अंग्रेजों को निकाला, उस समय इस देश में मुश्किल से 50 मिलियन टन अनाज पैदा होता था आज 133 मिलियन टन के दायरे में है। ढाई गुने से ज्यादा अनाज की पैदावार बढ़ाई गई। यदि कुछ दलों ने खेती सुधार कार्य को आगे बढ़ने दिया होता, अगर विकास कार्यों को ठीक ढंग से चलने दिया जाता तो आज मेरा विश्वास है कि हम कम से कम 270 मिलियन टन अनाज पैदा करते और और यह संभव हो सकता तो मेरा विश्वास है कि कम से कम 125 मिलियन टन अनाज हम गोरों की मंडियों में, यूरोप में भेज सकते थे। तेल से ज्यादा शक्ति रोटी में होती है और जो तेल की शक्ति का एक अटूट दबाव है दुनियां की अर्थव्यवस्था पर, वह हम पर नहीं होता। लेकिन यह करने नहीं दिया गया। कच्चे तेल का उत्पादन 1950-51 में मुश्किल से 6.6 मिलियन टन होता था अब 82-83 में करीब 21 मिलियन टन होने की आशा है। यह करीब साढ़े तीन गुना है श्रीमन। कोयले का उत्पादन 1950–51 में मुश्किल से 32.8 मिलियन टन होता था 1981–82 में यही बढ़ करके 124.9 मिलियन टन हो गया। लगभग चार गुना ज्यादा उत्पादन हुआ है। चीनी के उत्पादन का जहां तक सवाल है 1950–51 में मुश्किल से 11 लाख टन होता थी पैदा, 1980–81 में यह 84.35 लाख टन तक पहुंची है। श्रीमन, चीनी का उत्पादन आठ गुना से ज्यादा बढ़ा है। इस्पात का उत्पादन 10 गुना से ज्यादा बढ़ा है। 1950–51 में जहां फौलाद स्टील एक मिलियन टन पैदा होती थी वहां 1981–82 में 10.52 मिलिन टन हुई दस गुना से ज्यादा उत्पादन बढ़ा है। श्रीमन्, जहां तक सीमेंट का प्रश्न है मेरा निवेदन है कि सीमेंट के उत्पादन में भी 10 गुना से ज्यादा उत्पादन बढ़ा है। 1950-51 में सीमेंट 2.7 मिलियन टन मुश्किल से पैदा होती थी, 1982 में 22.48 मिलियन टन को पार कर चुका है।

बिजली का उत्पादन भी करीब-करीब बाईस गुना ज्यादा बढ़ा है और उसके आलावा दूसरे सभी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा—जहां तक एल्युमिनियम का सवाल है, 53 गुना ज्यादा उसका उत्पादन बढ़ा है।

जहां तक फर्टिलाइजर का सवाल है, वह भी करीब-करीब 90 लाख टन हो गया है।

श्रीमन, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें तरक्की नहीं की है। कपड़े का जहां तक सवाल है, एक समय वह इंग्लिस्तान से आता था, आज उसी इंग्लिस्तान में हमारा कपड़ा बिकता है। आज उसी अमरीका, कनाडा में हमारा कपड़ा बिकता है। आज यूरोप की मंडीयों में हिन्दुस्तान के कपड़े की पूछ है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र को ही ले लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में लिटरेसी को अगर लिया

[श्री बुद्ध प्रिय मौर्य]

जाए, तो मुश्किल से 16 फीसदी थी जिस समय हमने अंग्रेजों से आजादी प्राप्त की। आज साक्षरता करीब-करीब 36 प्रतिशत हो गई है। पुरूषों में ज्यादा है, महिलाओं में जरा कम है। दोनों को मिला कर घट जाती है। पुरूषों में तो करीब 46 प्रतिशत है।

1948-49 में प्राइमरी स्कूलों की संख्या मुश्किल से डेढ़ लाख थी! आज वह पांच लाख की संख्या को छू रही है। अंग्रेजों के जमाने में टूटी फूटी यूनिवर्सिटीज थीं जिनकी संख्या मुश्किल से 27 थी। आज इस देश में ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें दूसरे राष्ट्रों के विद्यार्थी भी आते हैं, प्रोफेसर भी आते हैं और आगे का अध्ययन करते हैं। उन यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 124 के करीब है। 112 युनिवर्सिटीज और 12 ऐसे टैक्नीकल इंस्टीट्यूट हैं, जिनको युनिवर्सिटी की कैटेगरी में जोड़ा जा सकता है।

SHRI KALYAN ROY (West Bengal): What about unemployment?

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA: I am coming to that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAT PAUL MITTAL): Please do not interrupt him. (*Interruptions*). Mr. Maurya, please carry on. I am the son of a labourer. (*Interruptions*).

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य: श्रीमन् मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि हमने हर क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। पब्लिक सेक्टर में भी, कहां, 29 करोड़ रुपए का इनवेस्टमेंट था, आप पब्लिक सेक्टर के बहुत प्रेमी हैं, इसकी तो कम से कम आप प्रशंसा कीजिए कि आज लगभग बीस हजार करोड़ रुपए का इनवेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर में है।

उद्योग के क्षेत्र में अगुवा राष्ट्रों के मुकाबले में—उन राष्ट्रों ने जिन्होंने हमें कालोनीज बना करके लूटा, आर्थिक व्यवस्था को जिन्होंने जर्जर कर दिया था, आज पैंतीस वर्षों के अरसे में उद्योग के क्षेत्र में, वह भारतवर्ष जो सदियों तक गुलाम रहा, वही भारतवर्ष आज दसवें नम्बर पर आता है।

टैक्नीकल नो-हाऊ के परसानेल की गिनती को लीजिये, तो दुनिया के तीसरे राष्ट्र में हमारी गिनती आती है। क्या यह उपलब्धि नहीं है? अगर यह उपलब्धि नहीं है, तो फिर उपलब्धि की परिभाषा हम आप से सुनना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि विरोधी दल के लोग बताये कि और दूसरे लोग देश के बारे में जरा बतायें कि किस तरह से यहां पर उपलब्धियां हुई हैं।

मैं बीस-सूत्री कार्यक्रम के बारे में निवेदन कर चुका हूं। मैं ज्यादा समय बीस-सूत्री कार्यक्रम पर नहीं लेना चाहता हूं। मैं समय लेना चाहता हूं भुखमरी और बेकारी पर क्योंकि मैं स्वयं अति सर्वहारा समाज में पैदा हुआ।

श्रीमन्, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मसले को इस सदन में और उस सदन में और सदन से बाहर भी हम लोग हमेशा से यह मांग उठाते रहे, लेकिन इस क्षेत्र में भी एक विशेष उपलब्धि हुई है। इस क्षेत्र की उपलब्धि के बारे में मैं कह सकता हूं कि वक्त हुआ करता था कि सेंक्रेटेरिएट में क्लास I में शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई अफसर नजर नहीं आता था। एक वक्त हुआ करता था कि किसी भी

जिले का कलक्टर शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब का नजर नहीं आया करता था ।

आई० सी० एस० की तो मानोपली हो गई थी, या तो इंग्लिस्तान के गोरी चमड़ी वालों की, या इस देश के अगुवा समाज की, लेकिन इस पैंतीस वर्ष के अंदर आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के आंकड़ों को अगर उठा कर देखा जाए तो करीब-करीब यहां अगर पूरी संख्या ली जाए, तो 4,138 आई० ए० एस० गिनती में आते हैं। इनमें से अकेले शेड्यूल्ड कास्टस से 417 हैं। शेड्यूल्ड कास्टस के संरक्षण के हिसाब से 15 फीसदी होना चाहिए । जहां शून्य थे, वहां पर आज 10.1 फीसदी है ।

इसी तरह से आई० पी० एस० में पूरी संख्या 2,184 के करीब आती है । उसमें से शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग करीब 219 हैं और वह भी 15 फीसदी होनी चाहिए । वह उपलब्धि शीघ्र होगी । लेकिन उसमें भी 10 फीसदी है । शून्य से 10 फीसदी पर आए ।

इनमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या भी 5.4 और 3.52 फीसदी आती है, जबकि उनकी 7.5 फीसदी होनी चाहिये। लेकिन यह उपलब्धि है । कहां तो वह जंगलों में रहते थे । आज हमारे शोषित समाज के बहिन और भाई सभ्यता के दायरे में आकर के इस देश में जगह-जगह पर कलक्टर और कमिश्नर बन रहे हैं ।

[उपसभाध्यक्ष, (श्री आर० आर० मोरारका) पीठासीन हुए]

उनकी संख्या भी आई० ए० एस० और आई० पी० एस० में 5.4 और 3.52 आती है ।

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात जरूर है कि एक कमी रह गयी है । जहां तक क्लास वन का सवाल है, क्लास वन में शेड्यूल्ड कास्ट की परसेंटेज अभी भी मुश्किल से 5 फीसदी है और शेड्यूल्ड ट्राइब की तो मुश्किल से 1 फीसदी है । मुझे विश्वास है कि जिन रास्तों पर हम चल रहे है उन पर चलते हुए हम शीघ्र ही इस क्षेत्र में भी कामयाबी के साथ आगे बढ़ सकेंगे ।

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने पड़ोसी राष्ट्रों के बारे में । अभी-अभी एक अखबार ने छाप दिया, बहुत ही भंयकर रूप से छाप दिया, वाशिंगटन पोस्ट ने छापा है, उस ने लिखा है कि हिन्दुस्तान के पास इतना प्लूटोनियम है, उन के पास इतना भंडार है कि 20 एटम बम हर साल बना सकता है। श्रीमन्, यह बहुत ही गैरजिम्मेदारी का बयान वाशिंगटन पोस्ट ने छापा है। भारतवर्ष का एक नियम रहा, यू० एन० का सम्मेलन हो, चाहे नान एलाइनमेंट की बैठक हो, चाहे सीक्योरिटी कौंसिल की मीटिंग हो, जहां कहीं भी हम को मौका मिला, हमने हमेशा कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स पर पूरे तौर से रोक लगायी जाये । हिन्दुस्तान की यह मान्यता रही कि कभी भी हम न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं बनायेंगे । यह हमारी मान्यता रही है और यह आज भी हमारी मान्यता है । दुर्भाग्य से अमेरिका के एक जिम्मेदार अखबार ने एक गैर-जिम्मेदार का समाचार छाप दिया । मैं इस का खंडन करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं ।

[श्री आर०आर० मोरारका]

श्रीमन्, जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का सवाल है, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत ने एक विशेष स्थान प्राप्त किया है। अभी-अभी समिट कानफ्रेंस "नान एलाइनमेंट" की भारत में होने वाली है। उसमें भारतवर्ष को नेता चुना जायेगा। यह भी एक सौभाग्य की बात है कि नान-एलाइनमेंट को जन्म देने वालों में भारतवर्ष का नाम था और आज फिर भारतवर्ष को नेता चुना जायेगा। मैं निवेदन यहां कर देना चाहता हूं। मैं दो प्रधान मंत्रियों का आपके सामने मुकाबला करना चाहता हूं। एक प्रधान मंत्री कलके, जनता पार्टी के थे, वे अमेरिका गये और एक आज की प्रधान मंत्री हैं, दोनों का अमेरिका में स्वागत हुआ—स्वागत के बारे में मैं कोई ज्यादा गलत-फहमी का शिकार नहीं होना चाहता, स्वागत अपनी जगह है—लेकिन जिस तरह का स्वागत भारत की आज की प्रधान मंत्री का हुआ शायद अमेरिका के इतिहास में इस तरह का स्वागत बहुत कम प्रधान मंत्री का हुआ है।

श्री शिव चन्द्र झा: पंडित जवाहर लाल नेहरू का बहुत बड़ा स्वागत हुआ था, मैं था वहां उस वक्त पर।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : मैं निवेदन यह कर देना चाहता हूं, कि मैंने अमेरिका का स्वागत नहीं देखा मैंने अमेरिका अखबारों को पढ़कर यह बात कही, उन अखबारों को पढ़कर बात कही है जिन से हम बहुत से विरोधी दल के नेता प्रेरणा लेते हैं। इतने बड़े स्वागत के बाद भी रीगन साहब को कहा गया कि हमारे पड़ोसी राष्ट्र को, जिसके साथ हम दोस्ती के सम्बन्ध चाहते हैं, दोस्ती का रिश्ता चाहते हैं हर कीमत पर, जहां आप एक तरह से, सोफिस्टीकेटेड वेपन्स का अम्बार लगा रहे हैं। यह भारत के पक्ष में नहीं और दूसरे भी इलाकों के पक्ष में नहीं है। एफ–16 जो अमरीका ने पाकिस्तान को दिये हैं, लेट सेविन्टीज की एडवांस्ड टेकनीक के साथ वह इतने ज्यादा सोफिस्टीकेटेड वेपन हैं कि वे इस क्षेत्र में इम्बेलेंस पैदा करेंगे। यह बात अच्छी नहीं रही, इसलिये अच्छी नहीं रही कि हमारे वह साधन, जिनके माध्यम से हम गरीबी की रेखा के नीचे गुजर करने वालों को भारत की मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं, जो साधन इसमें लगते कि उनको गरीबी के अन्धकार से बाहर लाया जाय, जिन साधनों से हम उनको रोजी-रोटी जुटाना चाहते हैं उन साधनों में कटौती करके हमें अपनी रक्षा पर खर्च करना पड़ेगा। एक तरफ तो यह प्रधान मंत्री थीं। और एक तरफ वे प्रधान मंत्री जनता पार्टी के थे जिन्होंने कहा कि भारत ने बहुत बड़ी गलती की जो राजस्थान में न्यूक्लियर इनर्जी का शान्तिपूर्ण तरीके से, निर्माण का कार्य करने के लिये ज्ञान प्राप्त करने का तजुरवा किया, हम वादा कर है कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। दो प्रधान मंत्रियों का यह आपस में मुकाबला करके देखो तो आप को अन्तर लगेगा। मैं जनता पार्टी के प्रधान मंत्री को अपना बुजुर्ग मानता हूं। उनका मैं भी सम्मान करता हूं, लेकिन दो का मुकाबला जब आप करते है उस समय क्या विचारधारा थी और आज क्या है तो अन्तर आप को लगेगा।

श्री सदाशिव वागाईतकर : बस यही रह गया।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : श्रीमन्, मास्को में भी स्वागत हुआ था जिसका जिक्र महामना राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है। वहां भी स्वागत हुआ। उस स्वागत में के संबंध स्वयं वहां के जिम्मेदार अखबारों ने छापा कि इस तरह का

स्वागत किसी समाजवादी राष्ट्र के किसी भी राष्ट्रपति का या किसी प्रधान मंत्री का नहीं हुआ । लेकिन इसके बावजूद आज के प्रधान मंत्री ने अपने मस्तिष्क का संतुलन नहीं खोया । उन्होंने कहा कि भारत की यह विचारधारा है, भारत यह चाहता है कि वह गुटबन्दी से अलग रहे । भारत चाहता है कि जितने फौजी अड्डे बड़ी-बड़ी ताकतों ने, बड़े राष्ट्रों ने दूसरे मुल्कों में बना रखे हैं वह हटाये जायें भारत यह चाहता है कि दूसरे मुल्क में गैर मुल्कों की फौजें न जायें और हम यह चाहते हैं कि वे कारण जिनकी वजह से...

एक माननीय सदस्य : सिवाय अफगानिस्तान और कंपूचिया के ।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : साथ ही साथ यह निवेदन-किया गया कि वे कारण जिन की वजह से अफगानिस्तान की सरकार को आप की फौजों की मदद मांगनी पड़ी, जिस समय वे कारण समाप्त हो जायें उस समय आप को अपनी फौजों को अफगानिस्तान से वापस बुला लेना चाहिये । यह देन है एक नेतृत्व की । मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं । मैं एक विचारधारा की, और सिद्धांतों की बात कर रहा हूं । कहां वे प्रधान मंत्री थे, किधर चले गये और कहां आज के प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने फिर से तटस्थ नीति, जो कि प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू की देन है, उस को मजबूती दी है और उसको बहुत शक्ति के साथ क्षमता के साथ आगे बढ़ाया है ।

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहूंगा डियागो गार्शिया के सम्बन्ध में नान-एलाइनमेंट समिट कांनफ्रेंस होने वाली है । मेरा विश्वास है कि उसमें इसका जिक्र जरूर छिड़ेगा । यह यू० एन० का रेजोल्यूशन है । यू० एन० ने रेजोल्यूशन किया है कि हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र माना जाये । दुर्भाग्य है कि हिन्द यहासागर शांति का क्षेत्र न बनकर अशांति का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है । वह एक तरह का मजबूत मिलिटरी बेस बनाया गया । डियोगो गार्शिया के सम्बन्ध में मेरे पास विस्तार से जानकारी है और इस पर यहां कई बार बहस भी हो चुकी है, लेकिन आज समय आ गया है कि डियोगो गार्शिया के बेस को जहां पर सोफिस्टीकेटेड वेपन्स बिछाये जा रहे हैं, जहां न्यूक्लियर वेपन्स का अम्बार लगाया जा रहा है और वह पायजनस गैस जो जापान से हटायी गई उसको वहां जमाया जा रहा है, उस डियागो गार्शिया के मिलिटरी बेस को समाप्त किया जाय ताकि यहां पर शांति का वातावरण पैदा हो सके ।

श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बहुत से मित्र जो इस समय भी बहुत बड़े दल के नेता बनते हैं, लेकिन उनका कोई बयान नहीं आया इस सम्बन्ध में । एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ; नर संहार हुआ लेबनान में और उस समय भारत सरकार और भारत सरकार के प्रधान मंत्री ने उसका खंडन भी किया, विरोध किया, और कहा कि एक तरह से यह हैवानियत का तरीका है । इस तरीके को नहीं अपनाना चाहिए उन्होंने कहा कि यह सभ्यता का तरीका नहीं है । लेकिन श्रीमन्, उस पर भी एक फाइंडिंग आ गयी । मैं चाहता हूं कि इसको भी आगे बढ़ाया जाय । मैं पढ़ना चाहता हूं :

"An international commission set up to investigate Israel's invasion of Lebanon has said that the Israli's are guilty of numerous violations of international law and Israeli Leadership should be tried for war crimes. The commission in publishing the report of its investigation recommended among other things that all

[श्री बुद्ध प्रिय मौर्य]

member nations of the United Nations suspend any financial or military support to Israel."

श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि इस पर भी सदन में जिक्र हो और जो सम्मिट कांफ्रेंस हो रही है उसमें भी इस पर जिक्र हो। मेरे मित्र कह रहे हैं कि गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं। इसमें शक नहीं कि एक बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी संख्या लोगों की आज गरीबी की रेखा के नीचे रह रही है। अभी भी इस देश में बड़ी संख्या उनकी है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि वे 40 फीसदी हैं आबादी का, कुछ कहते हैं कि आधे हैं---करीब 35 करोड़ और कुछ उनको आबादी का 60 फीसदी बताते हैं। लेकिन अगर उनकी आबादी आधी भी मान ली जाय तो वह एक बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी कहा जा सकता है कि हमारी कुछ उपलब्धियां भी हैं। तो आखिर कमी कहां रह गयी है। कमी रह गयी है उपलब्धियों को बांटने में। उसके डिस्ट्रीब्यूशन में कमी रह गई। इसी वजह से 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 हजार दुकानें इस देश में और खोली जा रही हैं जिसके जरिये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत बनाया जाएगा। उपलब्धियां हमारी हैं। यह एक नारा बहुत ही सही नारा बताया जा रहा है जो पढ़े लिख लोग तक देते हैं कि गरीब-गरीब होता जा रहा है और अमीर-अमीर होता जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं ....

एक माननीय सदस्य : यह झूठ है।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : यह नारा दे रहे हैं..... (**व्यवधान**) "यह जो नारा दिया जा रहा है कि गरीब और अमीर होता जा रहा है यह गलत है। इसका आधा हिस्सा गलत है। गरीब भी आगे बढ़ रहा है। और अमीर भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन अमीर तो आगे बढ गया और गरीब उसके मुकाबले पीछे रह गया। वास्तविकता यह है कि गरीब और गरीब नहीं हुआ है। गरीब का विकास हुआ है। पहले गरीब के शरीर पर कपड़ा नज़र नहीं आता था अब उसके शरीर पर कपड़ा नजर आता है। पहले गरीब के पैरों में जूता नजर नहीं आता था अब उसके पैरों में जूता नजर आता है। पहले जिनको प्याज की गांठ से खाना मुश्किल मिलता था---मैंने भी वह जीवन बिताया है---आज उनको प्याज की गांठ ही नहीं, रोटी के साथ दाल और सब्जी भी मिल जाती है। यह नारा बिल्कुल असत्य है और एक तरह से ऐसा पागलपन का नारा है जिसको कोई पढ़ा-लिखा समझदार व्यक्ति ठीक नहीं कह सकता है। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है यह गलत है। हमें गरीब और अमीर के बीच का जो फासला है वह बढ़ता जा रहा है। इस विषमता को किस तरीके से रोकें इस पर हमारी पूरी शक्ति लगी हुई है। गरीब और अमीर के बीच में जो फासला है वह दुर्भाग्य से बढ़ा है।

सबसे पहले मैं अपने विरोधी दलों के भाईयों से निवेदन करना चाहूंगा कि पहले वह इतनी क्षमता प्राप्त करें, पहले ऐसा नेता पैदा करें जिसके नेतृत्व में, जिसकी देख रेख में, जिसको नेता मान कर हिन्दुस्तान के 6 लाख गांव में कार्यकर्ता पैदा हो सकें। जब तक वह नहीं कर पायेंगे तब तक हिन्दुस्तान के हर गांव में पीने का पानी नहीं दे पायेंगे। जब यह नहीं दे पायेंगे तब क्या हिन्दुस्तान के हर जिले के गांव का विकास आप

कर पायेंगे मैं यह मानता हूं बहुत बड़ी संख्या में करीब करीब दो लाख के आस पास ऐसे गांव हैं जिनमें पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। लेकिन 6 लाख गांवों में से 4 लाख गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करा पाये हैं। (व्यवधान)

श्री हरीशंकर भाभड़ा (राजस्थान) : राजनारायण जी आपके नेता थे कैसे वहां चले गये।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : मेरे नेता नहीं थे, मेरे मित्र थे, मित्र हैं और मित्र रहेंगे। नेता आपके थे। वह बात करो जो जमे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि करीब चार लाख गांवों में पीने के पानी की सुविधा हम जुटा पायें हैं लेकिन अभी भी दो लाख गांव इस देश में ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी की सुविधा नहीं है। इस चुनौती को हमने स्वीकारा है। राष्ट्रपति जी ने, जो चुनौतियां हमारे सामने गरीबी की है, जो चुनौतियां हमारे सामने बेकारी की हैं, जो चुनौतियां हमारे सामने भुखमरी की हैं और जो चुनौतियां हमारे सामने हिन्दुस्तान के हर नागरिक को पीने का पानी उपलब्ध कराने की है, उनका जिक्र किया है। (व्यवधान) मैं निवेदन कर रहा था कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के शुरुआत में यह कहा गया है कि हमारे सामने चुनौतियां हैं। जहां हमारे सामने चुनौतियां हैं कि यहां कुछ लोग इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, जहां हमारे सामने चुनौतियां हैं कि कुछ लोग कानून से खेलने की साजिश कर रहे हैं, जहां हमारे सामने चुनौतियां हैं कि देश को किस तरह से एक रखा जाए, जनतंत्र को किस तरह से जीवित रखा जाए, किस तरह से समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त किया जाए, हिन्दुस्तान की एक बड़ी संख्या जो गरीबी की रेखा के नीचे है, गरीबी की रेखा के अंधकार में फंसी हुई है उसको किस तरह से गरीबी की रेखा के ऊपर रखा जाए, वहां उसके बारे में कार्यक्रम बनाये गये हैं। स्लम क्लीयरेंस का कार्यक्रम हम बना रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम भी बना रहे हैं कि किस तरह से दूर-दराज के इलाकों में पानी पहुंचाया जाए, जो बेपढ़े-लिखे लोग हैं, अभागे हैं मैं मानता हूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपलस में कहा गया है कि जो 14 वर्ष के बालक बालिका हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, यह पूरा नहीं हो पाया। मैं मानता हूं, लेकिन उसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा प्रयत्न जारी है। वे लोग जो बेपढ़े-लिखे हैं, चाहे वे बड़ी उम्र के हो गये हों उनके लिये पढ़ाने की व्यवस्था जारी की है किसी तरह से उनको ऐसी सुविधाएं दी जाय ताकि वे पढ़-लिख सकें। श्रीमन् मैं ज्यादा लम्बा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ हमारे मित्र बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गये। ऐसा लगा कि जब कभी भी उनके ऊपर कोई बात आती है तो ऐसा करने लगते हैं। हम सभी लोग चाहे हमारा संबंध किसी भी दल से हो, चाहे हमारी विचारधारा कोई भी हो, इस देश के दलों ने और इस देश के नेताओं ने निश्चय किया है कि जनतंत्र हमारा मार्ग होगा, समाजवाद हमारा लक्ष्य होगा। हमने निश्चय किया है कि पार्लियामेन्टरी डैमोक्रेसी हमारा वे आफ-लाइफ होगा और सोशलिजम हमारा डेस्टनेशन। हमने निश्चय किया है कि मसावात हमारी मंजिले मकसूद होगी, हम जम्हूरियत को लेकर चलेंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति में जो भी व्यक्ति हमारी मदद करता है, चाहे वह किसी भी

[श्री बुद्ध प्रिय मौर्य]

क्षेत्र से मिले, उसको हम आगे बढ़ाएंगे । लेकिन जो कदम इसको कमजोर करता है, मेरा निवेदन है कि उसको हमें रोकना पड़ेगा । आपने देखा कि आसाम में आन्दोलन भड़काना आसान था, लेकिन उसको आज सम्भालना मुश्किल हो रहा है । आप देख रहे हैं कि पंजाब में कुछ हवा दे रहे हैं । लेकिन याद रखिये भड़काना आसान होता है, उसको सम्भालना बहुत मुश्किल होता है ।

श्रीमन मैंने जहां से बात शुरू की गई थी वहीं पर समाप्त कर देना चाहता हूं । जैसा कि राष्ट्रपति जी ने कहा है, यह समस्या कोई अकेली सत्ताधारी दल की समस्या नहीं है, यह समस्या कोई अकेली सरकार की नहीं है । जैसा राष्ट्रपति जी ने कहा है, देश के सामने चुनौतियां भी हैं और हमारे सामने अवसर भी हैं । इन चुनौतियों और अवसरों, दोनों चीजों का मुकाबला करने के लिए संसद, सरकार और जनता, इन तीनों को आपस में सहयोग करना होगा, तभी जाकर लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा मुझे यही निवेदन करना था, धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Shrimati Margaret Alva to second the Motion. (*Interruptions*).

DR. RAFIQ ZAKARIA (Maharashtra): He gave you hell. (*Interruptions*).

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ (Madhya Pradesh): You should have some discipline.

SHRIMATI MARGARET ALVA (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir I rise to support the Motion of Thanks to the President.

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: What a fall.

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: What it this? Sir, on a point of order. When a lady Member is speaking...

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: You need not protect her. She is herself capable. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (Shri R. R. Morarka): Order please. Let the hon. lady Member continue.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Mr. Vice-Chairman ..... (*Interruptions*). Please let me start.

After the speech of my hon. predecessor, there is not very much left for me to say because he seems to have covered almost all the aspects that could have been covered by anyone. But there are a couple of points which I may have to repeat for lack of having anything to say as far as the President's Address is concerned. And I certainly share his concern at the attitude of some of the opposition parties who decide to boycott the Presidents Address this time. After all the President's Address is not a partisan address is the address of Parliament as a whole, and I think to insult the President is to insult in a way the nation and ourselves and I, think that does not do credit to ourselves...

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: There is a misunderstaning. The Opposition has written a letter to the President that this has nothing to do with the disrespect to the President.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Every party is going to have a chance to speak. You can speak when your turn comes. Why do you prevent others from speaking.

SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY (West Bengal): We are not preventing you.

SHRIMATI MARGARET ALVA: If you differ with what President had to come to the House and express your view and go on record. There was no need to make the Central Hall of Parliament...

SHRI GHANSHYAMBHAI OZA (Gujarat): Your party had boycotted Governor's Address...

SHRIMATI MARGARET ALVA: I am not yielding. I am not getting involved in State politics.

The country today is facing crises on many fronts. Some of these crises are perhaps man-made; some of them are nature-made; and some of them are imposed on us from outside. But all these factors together do create a situation in which we perhaps have got to think together and find a solution together.

Speaking about the political front, we see separatist forces on various fronts trying to resort to violence, unreasonable and partisan demands and narrow political responses from various sides. All these factors have tended to make most national problems into narrow political issues.

I would just mention two or three points. First I shall speak on Assam. So much has been said on Assam since yesterday. But I would be failing in my duty if I fail to mention this issue again. We know that this problem really started before the Congress Government came into power. You also had to handle it at some stage. (*Interruption*) Yes, it did start then. Janata Party will admit that it was a pre-Congress Government issue. I mean to say that it did not arise because of any particular party or any particular thing; it was a local issue which had started simmering even earlier. In 1978, election were held in Assam to the State Assembly. Those polls were considered good enough. Even though there were thousands of men, as you claim, who were there who should not have been there according to the present agitation leaders, yet the elections were held in 1978 and the Assembly was elected. And that Assembly certainly functioned in that State. Do you say that the 1978 electoral rolls were not valid, that they were made up, or they had to be rejected? Today when elections are being held on the basis of the same rolls, you say: "No, those rolls cannot hold good; they are not valid". On what ground do you say that that those 1978 rolls should not hold good for these elections.

SHRI JASWANT SINGH (Rajasthan): Very well argued.

SHRIMATI MARGARET ALVA: You can answer me if you can. You know things better. I am putting my point of view across.

I would say that negotiations have been going on. You have been involved. The Government has been involved. The students have been involved. Various formulae have been suggested them? And why did they reject ed them? And why did they reject them? At every stage when hopes seemed to dawn, the next day the students went back to Assam and said "No". This has hapened, you know, how many times. And the formula which seemed to go through was the formula which was presented by no less a person than your representative, Mr. Ravindra Verma. Every one was prepared to accept it—all of us. But what happened? Why did it go wrong? It was not accepted because the students decided that even that they did not want. So what was the alternative for us? Well, whether you want to admit it or not there was a choice for the Government—one of appearement or lonfrontation. And I am prepared to say today that a deliberate choice was made by the Government for appeasement for three years. But having chosen appeasement, you have to admit that confrontation was thrust on the government. Elections were declared as a part of the democratic process. If you believe in a democratic process and the functioning of the Constitution, then popular opinion of the people is the only answer when there is a deadlock. What the people were wanting had to be assessed. And how do you assess that except by a popular

[Shrimati Margaret Alva]

vote? It was up to the other parties to present an alternative to the people of Assam and say: "This is the other alternative, this is the other formula, this is what we believe the student's movement or the people of Assam should get." And it was up to the people of Assam, based on the 1978 rolls, to accept it to reject it. But if you say that the opinion is not to be taken and election is not to be held, then how do you assess public opinion in a democratic process? Is it by just listening to a student movement? I have nothing aga inst the students. They may have their grievances. They suffer from a sense of insecurity because they say they are being outnumbered. But, I believe, a sense of insecurity in any one section of the people of this country should not be allowed to destroy the democratic fabric or the democratic process accepted under the Constitution. After all, let us think also of the other side in Assam. You are dealing with human beings, thousands of them, men, women, and children who are part and parcel of the life of Assam over so many years, who came there not because, perhaps, they wanted to come but because political circumsatnces have compelled them to take refuge somewhere else.

We are a country who have given refuge to millions down the ages. We took the Tibetans. We took the responsibility when trouble came to Tibet. In my State we have whole settlement of the Tibetan people. They have not got citizenship rights but we have accepted them. We have taken thousands of people thrown out of Africa, people of Indian origin from Africa. They came from all parts, may be from Gujarat, originally; they have come from various parts and they have settled all over the country. They are coming from various sources. Why should we speak of a homeland for the Palestinians driven out of their home? We speak about the rights of the Tamil people in Sri Lanka. Can you just say that in one State, Assam, nothing holds good, the people have no rights to live, they cannot exist, you either shoot them or send them across the border or dump them in the Arabian Sea. Remember that this is a human problem. It almost sounds to me like Fascist Germany: You take the Jews and destroy them because you don't want them. They do not belong here. Where do you send them? They have no home. Where do they do? Would you say, destroy a whole people—millions of them—because you don't want them in Assam? Let ue not forget that we are talking about humanbeings, not about figures on a paper or a census sheet or just people who do not belong or do not exist. This is the tragedy of Assam. While one side has a say, I think, the other side has a right to exist.

Then I come to Punjab. Punjab is a State, perhaps, the number one economically, developed in every way. In fact, it has been the envy of most parts of the country. This is a State which we admire for the bravery of its people, for the contribution of these people down the centuries to the life of this country. And what is happening today? Is it really true that the mass of the people in Punjab are behind the sectarian, so-called, agitation, or, are we going to allow a group of religious leaders to make the whole issue into a political issue and hold the country to ransom? I know the talks are going to go on, negotiations are going to go on, and I don't want to raise any controversy on this. But all I can say is that I believe the time has come when all of us belonging to different States have got to think in terms of being Indians first and people of different States, languages and religious groups second. Only then can real, meaningful answers be found to our problems. In fact, resignations from Assemblies or boycott of these Chambers where expressions of opinion, exchange of views can take place is, I think, a very sad and very un-

wise decision because we would like to have our friends from these States to sit with us, speak about the issues and, perhaps, help find solutions to them rather than walk out of all democratic ways of finding solutions.

Mr. Vice-Chairman, Sir, a lot is said and we see it repeatedly in the papers, about the law and order situation in the country. It is tragic that every second day we read about clashes between communities, language groups, between castes and, will may be workers and various groups. I certainly distinguish when I speak about organised gangs of dacoits and so on which, of course, take their own legal course of being dealt with, but I might sound a little out of tune when I say that I do believe that these clashes that we see and hear about, particularly in the countryside, are a sign that things are beginning to change at long last I am one of those who believe that when there is a clash of this kind, it means that people who have been suppressed and oppressed and kept down for very long are no longer prepared to accept the situation as it exists and are beginning to fight back. I believe this is a positive sign of change and if there are certain vested interests in the rural side or in certain other parts who still try to keep the old order going, the clash perhaps becomes even more difficult; but it is bound to go on. And, therefore, to say that every clash is really a sign of the failure of the Government to keep the system going is, I think, not a correct assessment. But I do believe that there is need for us to reassess our local administration machinery, and particularly the role of the police as far as the local administration is concerned . Somehow we have new ideas, new systems growing, but without a basic change in the approach of the local administration and the police to the problems of the people. What was true of colonial India seems to hold good with the vast majority of them, who still believe that they are enemies of the people, to keep the people in their places. I would therefore, really plead for a complete review as far as police training is concerned, and a reform of the system as far as possible.

Look at Karnataka today. I do not see things are different because we have another Government there. You read of clashes in Bijapur, Bellary, Mysore and Bangalore. We have again seen the police beating the people. So it is not that you have a different Government, you have a different solution, a different answer to the solution of the problem.

The basic reasons remain the same when the Janata Government is in power there. There are some basic factors that create the same situation in different parts of the country, irrespective of which Government is administering at a particular time.

We have had a series of elections in the South, North-East, and in Delhi. And if you analyse the results, you will see that it is a complete reversal of the traditional voting pattern, whether it is North-Eastern India or South or it is in Delhi. In the South you had the non-Congress Governments and you experimented many things, and the result had been that regional parties had dominated the political scene for very long. We find the people gradually moving back to regional parties. It is a complete reversal of the voting pattern. I do not think this raises another problem. But all I can say is that everyone of us, whether in the Opposition or in the Government, all political parties...

SHRIMATI KANAK MUKHERJEE (West Bengal): And in Tripura?

SHRIMATI MARGARET ALVA: I refer to them. There has been reversal of the tradition voting patten. (*Interruptions*) O.K., except in Tripura. O.K., I correct myself. So what I would say that it is based on certain factors, and

[Shrimati Margaret Alva]

there is no point in saying so and so party has been pushed out, while many other parties are confronted with the same problem for various reasons in various States.

On the economic front, the new 20-point programme has placed before the country a programme which, if implemented, would solve many problems, particularly on the rural side. But I would venture, since I have to keep within a particular time ,to mention the main steps taken as a thrust on the rural front. And I mention in particular the National Rural Employment Programme, Scheduled Castes' Development Corporation, the Centrally-sponsored Scheme for Fishermen, and the Housing and Development Corporation and other set-up which aim at achieving certain concrete measures for the benefit of the weaker sections of the population.

As far as the development trends of the economy are concerned, I would like here briefly to quote a few figures for April-December 1982, as compared to the corresponding period of the previous year. The Economic Survey is out and I think we all have got copies of the same now. Power generation rose by 7.2 per cent; production of coal by 4.2 per cent; cement, by 10.2 per cent; fertilizers, by 9.6 per cent; and crude oil by 30.6 per cent. And here as far as the production of oil is concerned, I would like to give a comparative picture of the years between 1977 and 1978 when there was a rise of 1 million tonnes in the production of crude while between 1980 and 1983 there has been a rise of 11 million tonnes of crude from the previous period.

SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY: Have you got the figures?

SHRIMATI MARGARET ALVA: I have got the figures. I do not want to go too much into the statistics.

DR. RAFIQ ZAKARIA: Why do you want to disturb a good speech?

SHRIMATI MARGARET ALVA: You are all economic experts who can reply and break me down.

Mr. Vice-Chairman, as far as the foreign trade and balance of payments is concerned, we certainly suffer from the ill-effects which all developing countries are facing today due to unjust economic international order. And as you know, we pay more for our imports than we got for our exports, and the balance of payments position of the third world, developing countries, has always been an adverse one. But besides today we have the problem of having to spend even more on national security and arms because we have friends who believe that they have got to arm our neighbours so that these neighbours can be kept free and safe from us.

I would like to say a word about the public sector. There has been a great deal of criticism that the Congress Government is sliding back so for its commitment to the public sector is concerned. Well, I would like to say that the investment in the core sector, in the public sector, has been going up and not going down. Well, let us admit that historically we are, and we were all along, committted to a strong core sector in the public sector. But let us also realise that over the years we have been able to build an infrastructure. At Independence and immediately after it was a question of putting to the best use the limited resources, limited trained manpower and limited availability of raw materials. Over the years we have gained certain self-confidence as far as the core sector is concerned, and we are today in a position to diversify and allow other sectors also to make their contribution because we have today trained personnel, more domestic capital availability and certainly expertise in both domestic and foreign trade, and I believe that the maximum utilisation of all those have got to be given a chance to make their maximum contribution to the building up of the economy.

The public sector, I admit, suffers from many problems and shortcomings. We have had too long bureaucrats running our public sector undertakings. I think the time has come to build a good management cadre, the technocrafts, who will be really able to make a meaningful contribution to the public sector. And too many changes, frequent changes in the set up of these public sector units, the managements, and perhaps too much of red-tapism, do not allow them to function as efficiently and as easily as the private sector companies are able to do. And yet there has been a 21 per cent increase in the turn-over of the public sector companies in the country in the first nine months of the current financial year as compared to the previous year.

As far as science and technology is concerned, I would like to welcome the technology policy statement of the Government setting out the guidelines for development of the indigenous technology, and there is emphasis again on self-reliance in that field. I realise that we are still dependent very much on imported technology. But our target is self-sufficiency, and I hope that the Government will make sure that we stick to this and do not allow other factors to influence us. The second scientific expedition to the Antarctica is still there and we are proud of what we are achieving on this front. The present expedition is carrying on certain experiments, we understand from reports, for setting up a permanent manned station there.

Our work on the ocean floor has won us recognition and we have been recognised as a pioneer investor at the Law of the Sea Conference, a rare honour to a developing country. And in spite of our failure with INSAT-1A, INSAT-1B is planned to be launched in the current year which, it is hoped, will improve our telecommunication and meteorological capacity.

As far as Tarapur is concerned, I think it is a matter of great pride to all of us that this ticklish issue has been sorted out at last. Efforts had been made over the years to find a solution and to get the United States Government to stand by its commitments. In spite of all the problems that we have faced, we have now found a solution and supplies to Tarapur, it is believed, are to be resumed shortly.

Mr. Vice-Chairman, a couple of words on foreign affairs. We know that on many issues as far as our neighbours were concerned, we have been having problems for some time. But we are glad and proud that at long last, these issues have been brought down to the bilateral level from an international scene. On most issues we are able to talk with each other, rather than go to international forums and charge each other about something which really does not exist. So, as far as Pakistan, China and Bangaladesh are concerned, our various problems are being sorted out among ourselves and we hope that some kind of lasting understanding with these countries would be worked out. I for one have always been demanding that with Pakistan we would have to find a permanent solution, a permanent friendship in order that we might live in peace in the sub-continent.

Our support to the freedom movements in Africa has continued. Recently we welcomed in India Mr. Oliver Tambo, head of the African National Congress and the freedom movement there, and I am proud to say that for the first time anywhere in the world, he was accorded Head of State status, which is a recognition of the special place which that freedom movement occupies in the freedom struggle of that country.

We are on the eve of the Non-Aligned Meeting of Heads of State which promises to be the largest meeting of its kind ever held since the movement was born and we hope that the declarations from New Delhi will really mark a new phase in the history of that movement.

[Shrimati Margaret Alva]

There are many problems which are besetting the movement at the moment and it is hoped that at New Delhi these would be sorted out. The Commonwealth Heads of Government will also be meeting in India later in the year and this will bring New Delhi into international focus again. But in spite of all these meetings and efforts, the arms race goes on. There is talk on all sides of arms cuts but every nation seems to be stockpilling arms.

As far as the Indian Ocean is concerned, there seems to be no retreat in the position of anybody. As far as Afghanistan, the Iran-Iraq war and certain other issues are concerned solutions still seem to evade the international community. There is one issue which I find has not really been mentioned in the Address and that is the question of Indians abroad. I believe that Indians abroad today are one of the largest groups, perhaps both economically and politically the strongest group, of friends we have abroad. We can really tap this source not only on the question of development but also as far as goodwill is concerned, as our ambassadors abroad. There has been a great deal of neglect of them as those who ran away from this country at the most crucial time and failed to be part of the whole process of change. But now that we have set up a special cell to deal with the projects and the various suggestions of Indians abroad wanting to invest in India and wanting to start some kind of an industry in India. I hope that there will be more investments, more knowhow and expertise from these people coming into the national development efforts rather than borrow money from international institutions. If we can tap this great source of support, financial or otherwise, to our developmental efforts, I think many of our problems would be solved.

The question of health and family welfare is an important issue because in this country family planning has been accepted as a national programme by all parties, and I believe that whatever we do, unless and until a meaningful limiting of our numbers is achieved, no amount of effort on the developmental side will really show results. I believe this is something to which support from all sides should come forthwith in a more meaningful way.

As far as education is concerned, I am one of those who have been demanding over the years that a uniform national policy of education should be worked out. I don't see why our children should be educated with different textbooks in different parts of the country under different systems and different kinds of patterns of examinations and so on. I believe that we should at least now be able to work out something which would be acceptable to all, so that a uniform pattern could be evolved for the country.

There is one word which I have to say about women because nothing has been mentioned about them in the President's Address. It is really unfortunate because, I believe, that with the problems which women face in the country...

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: I am sorry it is left to you to mention it.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Why? Why are you objecting?

I agree that there have been various Amendment Bills brought in before Select Committees and various other forums dealing with the problems of women. But I believe that a package deal bringing all these amendments and making it once and for all possible of implementation, is required. Bringing this kind of amendments aimed at helping women, aimed at protecting them, aimed at sort of giving them a new right, piece-meal, is not going to solve the problem. I believe all these efforts have to be somehow or other made more comprehensive, brought together and imple-

mented speedily, if you want to improve the position of women in this country. The Dowry Prohibition Amendment Report has come before the House in the last Session. I hope that at least during this Session the amended Bill would come before the House so that at least now the possibility of unnecessary death and murder of young brides could be stemmed because this new amended law, we hope, will be able to achieve more.

Demand for family courts and legal reforms have been voiced in various quarters and I do believe that a certain amount of thought to these issues, including free legal aid, would have to be given.

In conclusion I have only an appeal to make. At a time of crisis like this what is needed is unity of purpose, discipline and rededication to a sense of nationalism. For too long have we been talking parties and party politics. I think the time has come when all of us in these august Chambers representing the people of this country should set an example and a trend that at least on national issues, on important issues, which threaten the integrity, the unity and the future of this country, that we as senior leaders —I do not call myself a leader—but at least leaders of political parties--sitting here, that we should all be able to sit together and be able to work out solutions which would be acceptable to the people of this country. After all, we come here not as representatives only of our constituencies or only of our State or only of our parties, we come here as representatives of the people of this country, and the people of this country expect a positive direction, positive solutions and a positive answer to the problems rather than bickering and differences day in and day out in Parliament.

[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

I would only appeal to you, I am sure you will agree with me that no problems of the nation can be solved in a day, in a decade or even in a generation. We would have to work for years and years in this country in order to achieve what we have set for ourselves to achieve. I think it is never too late to begin. Unless we commit ourselves now once again to rekindle this spirit of dedication in ourselves it might be too late. I would, therefore, say: let us begin our bit today so that the future of our country will be a more meaningful one.

4 P.M.

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members who have given notice of amendment may move them.

SHRI ERA SEZHIYAN (Tamil Nadu): Sir, I beg to move:

1. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to find a satisfactory solution to the issue of foreign nationals in Assam before ordering elections there.'"

2. "That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely—

'but regret that the Address does not mention about making elections in Assam a mockery of democratic process caused by an atmosphere of indiscriminate repression and terrorism.'"

3. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to find a satisfactory solution to the legitimate demands raised by the Akalis in Punjab.'"

4. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not mention about the fail-

[Shri Era Sezhiyan]

ure of the Government to root out corruption and to bring to book the corrupt in high places in Government and public enterprises.' "

5. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to give remunerative prices for agricultural produce and establish price parity between agricultural and industrial products.' "

6. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not mention about the unfair practice of the Government in hiking the prices of petroleum products just before the commencement of a Parliament session.' "

7. "That at the end of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to bring down the rising prices of essential commodities affecting the common man.' "

8. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to bring to an end the prolonged textile strike in Bombay.' "

9. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to give adequate and timely relief to drought affected areas in the country.' "

10. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to arrest violence and injustice to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes; backward-communities and minorities.' "

11. "That at the end of the Motion, the following be added namely.—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to curb, by legislative and administrative measures, the incidents of rape and assault on women.' "

12. "That at the end of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to curb incidents of communal disturbances and disharmony.' "

13. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to arrest the deteriorating situation in industrial relations and to ensure minimum and fair wages to the working class.' "

14. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not mention about the steps to be taken for strengthening the federal structure and devolving the resources and power from the Centre to the State and Panchayat levels by clear constitutional measures.' "

15. "That at the end of the Motion, the following be *added* namely—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to initiate steps for electoral reforms including enactment of an anti-defection law.' "

16. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to ensure distribution of essential commodities at fair prices to all weaker sections.'"

17. "That at the end of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not mention about the new Industrial policy which favours big houses and monopoly interests.'"

18. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not mention about the misuse of Government machinery during elections.'"

19. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to implement the recommendations of the Mandal Commission.'"

20. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to arrest the growing intolerance and repression of the Press in the country.'"

21. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not mention about the misuse of the mass media like Radio and T.V. to subserve the interests of the ruling party.'"

[Amendment Nos. 1 to 21 also stood in the names of Shri Sadashiv Bagaitkar, Shri Manu Bhai Patel, Dr. M. M. S. Siddhu, Shri Sushil Chand Mohanta and Dr. Mahabir Prasad].

SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY: Sir, I beg to move:

22. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address fails to mention the steps to be taken for immediate solution of the labour problem in the country in general and the Bombay Textile Workers' strike in particular.'"

23. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address fails to declare the scrapping of the anti-people and anti-labour legislations *viz.* ESMA and NSA as demanded by the Trade Unions and to drop the proposed legislation concerning employees of Educational Institutions and Hospitals.'"

24. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not mention about the early settlement of labour disputes in Coal Industry and Public Undertakings.'"

SHRI JASWANT SINGH: Sir, I beg to move:

25. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not take serious note of the fact that elections in India are becoming more and more expensive which is dangerous for the democratic system and that Government instead of taking active interest in bringing about electoral reforms, is evading a decision on such reforms year after year on one or other pretext.'"

26. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not contain any assurance to the retired Government pensioners that none of them will be paid

[Shri Jaswant Singh]

pension less than the minimum wages.'"

27. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not express any concern over the very disappointing promotional avenues for the Army, Navy and Air Force officers and personnel and also over the fact that the pay scales in several categories are less than those available to the civilians in the equivalent categories.'"

28. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not express its concern over the serious situation that the houses and the school buildings constructed by the D.D.A. are crumbling even before they are put to use and the construction defects are also not rectified in spite of several complaints.'"

29. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not express any anxiety over the fact that the Government have ignored the direction of the Supreme Court that the large number of under-trials who have already remained in jails for more than the period they would have been otherwise sentenced. should be released.'"

30. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not contain any assurance for the protection of the interest of the farmers and that the prices of the agricultural commodities will be fixed in proportion to the cost of inputs.'"

31. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not refer to the inability of Government to resolve the Bombay Textile Workers' strike which is going on for a long time and nor does it contain any assurance for providing a time-bound relief to lakhs of families of the workers effected by the strike.'"

32. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not show any concern over the failure of the Government to bring about a satisfactory solution to the Punjab problem.'"

33. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not express concern over the fact that the elections held in Assam recently were neither free nor fair.'"

34. "That at the *end* of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not refer to the wide-spread violence and incidents of arson which have taken place in Assam because of the imposition of elections inspite of public protests and wide-spread demonstrations'"

35. "That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely—

'but regret that the Address does not express concern over large scale misuse of Government machinery in the recent elections in Andhra Pradesh, Karnataka, Tripura and Delhi.'"

[Amendment Nos. 49 to 59 also stood in the names of Dr. Bhai Mahavir, Shri Hari Shankar Bhabra, Shri Jagdish Prasad Mathur and Shri Pyarelal Khandelwal].

श्री शिव चन्द्र झा : श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

60 "प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये अर्थात् :—

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मैथिली को भारत के संविधा

की आठवीं सूचि में सम्मिलित करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है ।"

61. "प्रस्ताव के अन्त मे निम्नलिखित जोड़ा जाए अर्थात् :-

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन लोगों के नामों को निकाले बिना जो भारतीय नागरिक नही हैं, असम में बलपूर्वक चुनाव थोपे जाने के कारण हुई व्यापक हिन्सा तथा खून खराबी के बारे मे कोई उल्लेख नहीं है।'"

62. "प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

'किन्तू खेद है कि अभिभाषण में सरकारी प्रशासनिक तंत्र के दोषयुक्त रूप से कार्य करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है ।'"

63. "प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार में कानून और व्यवस्था के ठप्प हो जाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है । '"

64. "प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए अर्थात् :—

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण मे बिहार उड़ीसा और तमिलनाडु के प्रेस विरोधी कानूनों को वापस लेने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।'"

65. "प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण मे इस बात का कोई उल्लेख नही है कि देश में अमीर अधिक अमीर होता जा रहा है और गरीब अधिक गरीब होता जा रहा है।'"

66. "प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

'किन्तु खेद है कि अभि भाषण में देश में आय में बढ़ती हुई असमानताओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'"

67. "प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण मे देश के बड़े एकाधिकारी घरानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।'"

68. "प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।'"

69. "प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में भूमि सुधारों के त्वरित क्रियान्वयन की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'"

70. "प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण मे पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर परमाणकीय तैयारी किये जाने के फलस्वरूप देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाने को ध्यान में रखते हुए देश की परमाणु

[श्री शिव चन्द्र झा]

नीति के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है ।'"

71. "प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

'किन्तु खेद है कि उप-महाद्वीप में स्थायी रूप से शान्ति स्थापित करने के लिये भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांगलादेश तथा बर्मा के परिसंघ, के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है ।'"

72. "प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :-

'किन्तु खेद है कि देश में संविधान द्वारा अपेक्षित समाजवाद की स्थापना किये जाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है ।'"

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): Sir, I beg to move:

75. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the role of U.S. imperialism on the question of arms supplies to under-developed and developing countries.'"

76. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the conspiracy of the U.S. imperialism to crush the democratic movements in various countries.'"

77. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the enormous increase in U.S. defence expenditure causing increased threat to the World peace.'"

78. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the fighting people of Angola, Ethiopia, Mozambique and the People's Democratic Republic of Yeman.'"

79. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the danger of war in place of detente and armament agreement.'"

80. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the massive anti-war rallies that have been held in different parts of India including Delhi.'"

81 "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the danger of nuclear war threatening humanity because of the criminal policies pursued by the U.S. imperialists.'"

82. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the call for an urgent task of the working class and all progressive sections to combat nuclear war danger, expose and unmask the imperialists plans before the people to save the world from nuclear destruction.'"

83. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the

plans of the U.S. imperialists for global domination, using various agencies.'"

84. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the fact that at the direct instruction and incitement of the USA, Israel played havoc on the heroic Palestinian forces in Lebanon and caused genocide among the Lebanese people.'"

85. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the crisis of the capitalist system of development in the world and its inevitable consequences experienced by the Third World countries.'"

86. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the anti-imperialist forces actively fighting the imperialists in El Salvador, Nicaragua, Zimbabwe, Namibia and Southern Africa.'"

87. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the fact that the inflationary spiral has been continuing without check for nearly a decade and has become a permanent feature of the Indian economy.'"

88. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the high prices imposed by oil monopolists, taking advantage of the price-increases made by the oil producing countries, having contributed further to this process.'"

89. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the role of World Bank and the International Monetary Fund agencies who are instrumental in accentuating the inflationary spiral, through their demands on the Indian Government to raise taxation levels, raise oil and fertiliser prices, and reduce people's consumption standards.'"

90. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the burden of debt services despite rapid rise in the export earnings and the enforced exports and dependence on Western countries leading to unparalleled loot of the country.'"

91. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the fact that the World Bank has been pressing India to go for commercial borrowing for financing its plans, abandoning the import substitution policy and follow an active export promotion policy—a policy to divert goods from the internal to the external market.'"

92. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the continuous defying of Government directives regarding dilution of equity by the drug and other multinationals.'"

[Shri Dipen Ghosh]

93. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure to undertake radical land reforms policies.'"

94. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the exploitation of agricultural workers, and the absence of any genuine legislation to protect their wage standards.'"

95. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the remunerative prices to the peasants.'"

96. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the percentage of people below the poverty line.'"

97. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the process of mass eviction from land resulting in the increase in the ranks of labourers.'"

98. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the housing problems in the urban and rural areas.'"

99. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the increasing problems of the slum population.'"

100 "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the concentration of land in the hands of a few.'"

101. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the mounting prices causing intense suffering to all sections of the people particularly the workers in unorganised industries, the agricultural workers and peasants.'"

102. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the extension of Government's fullest solidarity to the people of Pakistan and Bangladesh who, facing the most brutal repression of reactionary regimes, are fighting courageously for the restoration of democracy in their countries.'"

103. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the strengthening the Indo-Soviet Treaty of Friendship and Cooperation which is a big lever to ward-off imperialist military pressures and defeat aggression.'"

104. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the general breakdown of law and order situation in the country.'"

105. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the deteriorating situation due to growing collusion between the police, the bureaucracy and the anti-socials.'"

106. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the attack on the freedom of the trade union movements and the right to organisation.'"

107. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the Government's intimidation of the Press and introducing a kind of censorship of news.'"

108. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the growing attacks on the constitutional powers of the States and concentration of powers in the Centre.'"

109. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the concerted and deliberate efforts to undermine the judiciary.'"

110. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the real upliftment of Harijans and Scheduled Tribes.'"

111. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the propagation of separatism in the Adivasi areas of the country.'"

112. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the Adivasis being deprived of human existence and sold as bonded labour; their young girls sold in the flesh market, alienated from the rest of the country; their common democratic struggle; their areas are providing ideal ground for some foreign Christian missions to spread the message of separation from the country.'"

113. "That at the end of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not mention about the mischief of Christian missions in the North-Eastern region resulting in secessionst feelings in the area.'"

114. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of

[Shri Dipen Ghosh]

the Government to fight and expose the machinations of the foreign Christian missions in the North-Eastern region.'"

115. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to fight the Islamic fundamentalist appeal which is directed towards creating a feeling of separate nationhood among the Muslims to undermine national unity.'"

116. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the fact that the Government is afraid to fight the separatist and anti-Indian-unity propaganda because it does not want to offend the reactionary rulers of certain oil-producing countries.'"

117. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the problems of minorities.'"

118. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the chauvinistic appeal of the RSS in terms of a Hindu Nation becoming a provocative agency of imperialism to drive the Muslim mass into the camp of the fundamentalists.'"

119. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the Indian women who are victims of an obscurantist semi-fedual outlook and, despite the equality of sexes proclaimed in the Constitution they are denied equal treatment, including equal wages.'"

120. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the increased number of incidents of rape and molestation of women.'"

121. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the severe attacks on Harijans, tribals in the country-side and utter failure of the Administration to prevent such atrocities.'"

122. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to nationalise foreign banks, monopoly houses and branches of multi-national Corporations.'"

123. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the sale of essential commodities such as foodgrains, edible oils, cloth, sugar etc. at subsidised prices through a net work of shops in the public distribution system under the conrol and supervision of popular committees by ensuring adequate and uninterrupted supply of these commodities.'"

124. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the importance of real federal character of our country.' "

125. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the wage policy towards granting a living wage to the workers.' "

126. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to consider ways and means to check the ravages caused by repeated floods and droughts.' "

127. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the fresh constitutional provisions to expand powers of the States and guarantee their autonomy.' "

128. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the deletion of Articles 356 –360 of the Constitution.' "

129. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the inclusion of the right to work as a fundamental right in the Constitution.' "

130. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the anti-eviction measures; guaranteed fair prices for peasants' produce; supply of cheap credit and subsidized inputs to the mass of the peasantry.' "

131. "That at the end of the Motion, the folowing be added, namely:—

'but regret that the Address not mention about he planned and independent development of the national economy free from foreign influence.' "

132. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the importance and significance of the role of the public sector in the foreign influence.' "

133. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the just and equitable incomes and wage policy based on provision of minimum conditions like need-based income to the mass of people and reduction of the monstrous disparity in the incomes of the big capitalists and landlords and the mass of people.' "

134. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the pension for aged agricultural workers.' "

135. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the allotment

[Shri Dipen Ghosh]

of free house sites to the agricultural labourers and poor peasants and the semi-proletariat and liberal provision for cheap credit and consumption loans.'"

136. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the adequate educational facilities for peasant masses.'"

137. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about a massive plan for full employment to the rural unemployed and unemployment relief.'"

138. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the lock-outs, lay-offs and closure of mills.'"

139. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the taking over of all closed mills.'"

140. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about granting full trade union rights to Central and State Government employees and abolition of the police verification system.'"

141. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about anti-working class laws.'"

142. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the introduction of automation and other measures aggravating unemployment.'"

143. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the immediate introduction of free education upto the secondary stage in all States.'"

144. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the provision of hostel facilities and full scholarships for all needy students.'"

145. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the special attention to the requirements of Scheduled Tribe and Scheduled Caste students.'"

146. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the right of students to be represented in academic bodies for thorough-going reforms.'"

147. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the need for radical changes in education making it democratic, secular and scientific'."

148. "That at the end of the motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the need to take drastic steps against those who indulge in ourages against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes'."

149. "That at the end of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not mention about taking immediate steps to put an end to the economic and social oppression of Scheduled Castes and Scheduled Tribes people by landlords, contractors and restoration of lands seized by them'."

150. That at the end of the Motion the following be added, namely:—

'but regret that the address does not mention about the reservation of jobs and special facilities in matters of educational and economic advancement of Scheduled Castes and Scheduled Tribes people'."

151. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about safeguarding the rights of Muslim minorities against discrimination in Government services and educational institutions and against Urdu.'"

152. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the inclusion of Nepali, Maithili, Manipuri and Dogri languages in the Eighth Schedule to the Constitution of India.'"

153. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the full support to the freedom struggle of the Namibian and other African people against imperialism, apartheid and racial domination'."

154. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the right to exercise franchise on attaining 18 years of age as a fundamental right of the people of India.'"

155. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the constitutional amendments for equal representation in the Rajya Sabha to all States and Union Territories having a population of over three million, on the scale of 6 members each and to States and Territories having less, 4 members each.'"

156. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the right to bear small arms as a fundamental right of the citizens.'"

157. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the abolition of casual system of employment amongst seamen and

[Shri Dipen Ghosh]

guarantee to them employment throughout the year.'"

158. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to take stringent measures against black-marketeers, hoarders, smugglers, speculators and officials protecting them.'"

159. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the rectification of fraudulent cost of living indices.'"

160. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the need to reduce work load and duty hours of railway employees'

161. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the refusal of the Government to revise wages of Central Government employees for the past seven years resulting in decline of wages of the employees by 7 to 37 per cent during the last eight years.'"

162. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to implement the recommendations of the Third Pay Commission for wage revision after the consumer price index crossed the 272 mark.'"

163. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the recognition of trade unions through secret ballot.'"

164. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the series of railway accidents and loss of thousands of lives.'"

165. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to fully implement the Directive Principles of the Constitution of India.'"

166. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the woeful lack of medical facilities and the primary health centres in the vast majority of the villages in the country.'"

167. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the need for the abolition of bonded labour in the country.'"

168. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the abolition of contract labour system in the country.'"

169. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the

failure of the Government to improve sports standards in the country.'"

170. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the need for the nationalisation of drug industry in the country.'"

[Amendment Nos. 75 to 170 also stood in the names of Shri K. Mohanan, Shri Nirmal Chatterjee and Shri Arabinda Ghosh].

SHRIMATI KANAK MUKHERJEE (West Bengal): Sir, I beg to move:

171. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the implementation of the agreement made with the Federation of Port and Dock workers in January, 1981.'"

172. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the steps to be taken expeditiously to guarantee the employment of seamen and payment of wages to them as recommended by the I.L.O.'"

173. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Parliamentary norms by Government in hiking the prices of ease the traffic congestion.'"

174. "That at the end of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not mention about the flouting of the Parliamentary norms by Government in hiking the prices of petroleum products on the eve of the Budget Session of the Parliament.'"

175. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the stepmotherly attitude of the Government towards the entire eastern region of the country with regard to the Industrial development.'"

176. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the protracted strike of the textile workers of Bombay due to Government's reluctance to solve the problems involved therein.'"

177. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the import liberalisation policy adopted by the Government to the detriment of the industrial development within our own country.'"

178. "That at the end of the Motion, the following be added namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to introduce a comprehensive Industrial Relations Bill in consultation with various trade union organisations.'"

179 "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the much-talked of Joint Consultative Machinery which has virtually been

[Shrimati Kanak Mukherjee]

made ineffective in so far as the settlement of disputes are concerned.'"

180. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to consider the working of the Law Commission effectively.'"

181. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to make arrangement for payment of bonus to all Central Government employees without any discrimination.'"

182. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the Central Government employees who are being subjected to dismissals, suspensions, criminal cases, fines, pay-cuts, break-in-services etc. in utter disregard of their trade union rights.'"

183. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to provide necessary help to the States and Union Territories for supply of drinking water to the poor.'"

184. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to take suitable action on the 16-Point Charter of Demands presented to the Central Government by the people of West Bengal through their 'Pada-Yatra' in June, 1982.'"

185. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about delay in the setting up of a power generation plant at Mejia, Bankura in West Bengal by the Central Government.'"

186. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the failure of the Government to nationalise the jute, textile and cement industries in the country.'"

187. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about inordinately delaying the process of starting Petro-chemical complex at Haldia by not rendering all necessary help to the Government of West Bengal.'"

188. "That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

'but regret that the Address does not mention about the disparities in regard to fixation of quota of raw materials for the States.'"

(Amendment Nos. 171 to 188 also stood in the name of Shri Harkishan Singh Surjeet)

The questions were proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Motion and the amendments moved will now be open for discussion. The discussion will continue tomorrow.